प्रमक्त

राधा रतूड़ी, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

संवा में

निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 🗸 अगस्त, 2007

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में आई०सी०डी०एस० से संबंधित अनुदान संख्या-15, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय.

वित विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 599/XXVII(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वालू वितीय वर्ष 2007–08 के आय—व्ययक में आई०सी०डी०एस० से संबंधित अनुदान संख्या—15, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनशशियों को संलग्नक के अनुसार कुल रुपये 90,59,76,000.00 (रूपये नब्बे करोड़ उनसद लाख छियतर हजार मात्र) की धनशिश को चालू वितीय वर्ष 2007–08 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहध स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

 अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर

केशपलो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

 आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

 उबल आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय

अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंविटत धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकरिंमक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लधु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में वाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या—15, 30 एवं 31 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

 रांलम्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्वित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं

व्यय की रिश्रति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

भितव्यययता के संबंध में नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

 यदि किसी अधिष्ठान / योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का अवित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या— 599 / XXVII(1) / 2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 में उल्लिखित अन्य शर्तों एवं दिशा—निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- बचनबद्ध मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक अनुमोदन / स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्वित किया जाएगा।

 अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय—सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

12. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।

13. बी०एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें।

14, इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15, 30 एवं 31 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

15. उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के अ०शा० पत्र संख्या २५५१)/वि०अनु०-०३/२००७. दिनांक ७७ ०७ १० २००७ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय, (राधा रतूड़ी) राचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1/32(1)/XVII(2)/2007 तद्विनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

निजी सचिव–मा० गुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

- 2 निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
- जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—03, उत्तराखण्ड शासन।
- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सविवालय परिसर, देहरादून।
- 14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से.

